शिल्पियों के लिए वित्तीय सहायता

7899. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पारंपरिक कलाओं को अक्षुण्ण रखने के लिए हस्त शिल्पियों/शिल्पियों को वर्ष 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान किसी भी राज्य सरकार तथा इसके अभिकरणों से परम्परागत शिल्पों के परिरक्षण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, 1994-95 के दौरान लुप्तप्राय: शिल्पों के पुनर्जीवन के लिए निम्नलिखित राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों से 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :--

निगम का नाम	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	शिल्पों का नाम
मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, भोपाल	5	जन जातीय मुखोटे, सहारिया चित्रकारी, लघु चित्रकारी, कलात्मक आभूषण तथा पत्थर शिल्प ।
आन्ध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, हैदराबाद	4	तेलिया रुमाल, चमड़े की कठपुतली, वीणा तथा मृदंगम बनाना ।

(ग) सरकार ने मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम तथा आन्ध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के सभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं ।

कपास का उत्पादन

7900. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विद्युत करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों में कपास की पृथक-पृथक् कुल कितनी खपत हुई ;

(ग) सरकार ने हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र में कपास का कोटा आवंटित करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं ;

(घ) कपास के पिछले बकाया भण्डार की अनुमानित मात्रा कितनी है, जो आगामी वर्ष के दौरान उपलब्ध होगी ; और

(ङ) सरकार ने कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) पीछले तीन वर्षों के दौरान कपास का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है :—

राज्य	1991–92	1992–93	1993–94
पंजाब	23.71	23.00	14.00
हरियाणा	14.06	14.06	10.00
राजस्थान	10.23	11.50	11.00
गुजरात	15.16	22.62	19.00
महाराष्ट्र	12.48	20.50	14.00
मध्य प्रदेश	08.94	08.50	14.50
आंध्र प्रदेश	18.82	19.07	23.50
कर्नाटक	8.85	9.75	9.00
तमिलनाडु	5.75	5.00	5.50
अन्य	1.00	1.00	1.00
कुल :	119.00	135.00	121.50

(ख) हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र सीधे कपास की खपत नहीं करते हैं वे कपास से मिं धार्न का प्रयोग करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान 85.4% यार्न प्राप्त करने को मानते हुए हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा कपास की खपत निम्नानुसार है :—

	हथकरघा क्षेत्र		विद्युतकरघा क्षेत्र	
	(सूती यार्न की खपत)	कपास की मांग	सूती यार्न की खपत	कपास की मांग
1991-92	382	382(22.6)	719	841(49.5)
1992-93	377	441(25.9)	823	964(56.7)
1993-94	422	494(29.1)	903	1057(62.2)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े लाख गांठ में हैं--प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम।

(ग) सरकार हथकरघा और विद्युत-करघा क्षेत्र के लिए कपास का कोई कोटा आबंटित नहीं करती है ।

(घ) कपास सलाहकार बोर्ड के प्राक्कलनों के अनुसार इसके लगभग 26.2 लाख गांठ--प्रत्येक गांठ 170 किग्रा० होने की संभावना है ।

(ङ) कृषि मंत्रालय विभिन्न कपास उपजाने वाले राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रयोजित गहन कपास विक.स कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन राज्यों को प्रजनक आधार का उत्पादन करने तथा प्रमाणिकृत बीज, प्रमाणीकृत बीजों का वितरण तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए इन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

Closure of small-scale Textile Industries

7901. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether a number of small scale textile industries have been closed due to non-availability of yarn;

(b) if so, the number of such small scale textile industries closed from 1st January to May. 1995. month-wise;

(c) what action has been taken to reopen these mills; and

(d) if no action has been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Export of wooden handicrafts

7902. SHRI BHAGABAN MAJHI; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up any programme for revival and modernisation of Kashmir silk;

(b) if so, whether that plan has been approved by the Central Silk Board?

(c) if so, the quantum of funds earmarked therefore; and

(d) the steps taken to implement the proposal?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) A World Bank/Swiss Deve lopment Cooperation assisted National Sericulture Project (NSP) is already being implemented in Jammu & Kashmir for promotion of modern sericulture practices and strengthing of sericulture infrastructure in the State:

The Jammu & Kashmir Industries Ltd., have sought assistance for modernisation of the existing two silk reeling units (filatures) in the State. The total capital cost envisaged for this programme including assistance sought under NSP is Rs. 156.50 lakh?. The Central Silk Board (CSB) had sought certain clarifications which have been received recently and the Board has now to take a view in the matter. Meanwhile, with a view to encourage modernisation of Silk production in the State, the CSB has initiated action to supply two units of 10 end Central Silk Technological Research Institute (CSTRI) multiend reeling machines to the State of Jammu & Kashmir.